राजस्थान की राजनीति में विभिन्न जातीय समूहों की भूमिका

***कैलाश चन्द्र बुनकर**

सारांश:

वर्तमान में भारतीय राजनीति में जातिवाद का प्रभाव निरंतर बढ़ रहा है और यह अनेक कारकों से प्रभावित हो रही है। यह जातिगत राजनीति राष्ट्रीय स्तर से लेकर राज्य स्तर पर भी फैलती नजर आ रही है और राजस्थान भी इससे अछूता नहीं है। राजस्थान की राजनीति को भी अनेक जातिगत समूह प्रभावित कर रहे हैं। राजस्थान की राजनीति में जातीय समूहों का प्रभाव राजस्थान के गठन के बाद से ही स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है तथा ये दोनों एक-दूसरे से गहरे रूप में जुड़े हुए हैं और एक-दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। प्रस्तुत शोध राजस्थान की राजनीति में जातीय समूहों की भूमिका और उनके प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करता है

प्रस्तावना:

स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात् भारतीय राजनीति का आधुनिक स्वरूप विकसित हुआ। अतः यह संभावना व्यक्त की जाने लगी कि देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित होने पर भारत से जातिवाद समाप्त हो जायेगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ; बल्कि जातिवाद ने न केवल समाज में बल्कि राजनीति में भी प्रवेश करके उग्र रूप धारण

*व्याख्याता, लीलावती कॉलेज ऋषभदेव, उदयपुर (राजस्थान)

कर लिया है। भारत में जातिवाद ने न केवल यहाँ की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक प्रवृतियों को ही प्रभावित किया है, बल्कि राजनीति को भी पूर्ण रूप से प्रभावित किया है। भारत की राजनीति में जाति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। केन्द्र ही नहीं राज्यस्तरीय राजनीति भी जातिवाद से प्रभावित है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि इसके कारण राष्ट्रीय एकता एवं विकास मार्ग अवरुद्ध हो रहा है।

भारतीय राजनीति में जातिवाद:

भारतीय राजनीति के प्रमुख मुद्दों में जातिवाद सर्वोपरि है, जातिवाद किसी न किसी प्रकार हमारी राजनीति को प्रभावित करती है, संविधान निर्माण के समय से ही इनमें कुछ सुधार किये जा रहे हैं, कभी किन्हीं राजनेताओं के द्वारा तो कभी सुधार प्रस्ताव के द्वारा जातिवाद नामक मानसिकता को सुधारने का प्रयास किया जाता रहा है। इसका गवाह इतिहास स्वयं है। आज राजनीति में या मनुष्य के जीवन को यदि सबसे ज्यादा प्रभावित कुछ करता है तो वह जातिवाद है। इसकी जड़े प्राचीनकाल से ही इस कदर भारतीय राजनीति में जमी हुई है कि इसे निकाल फेंकने का प्रयास भर मानव मात्र कर पाया है। तमाम प्रयासों के बावजूद भी भारतीय राजनीति में अपनी जड़ों को जमाये हुए हैं, जो वर्तमान राजनीति में एक भयंकर बीमारी प्रतीत होता है। हमारे समाज में एक बड़ी ही व्यापक और मुख्य भूमिका अति पिछड़ों तथा दलितों की है, दलितों का हमारे जीवन में प्राचीन काल से ही विशेष भूमिकाएँ रही हैं, ये समाज के ऐसे वर्ग है, जो अपना एक अलग महत्व रखते हैं, अब प्रश्न ये है कि ये दलित आये कहाँ से इसकी

जड़ में जातिवाद है। भारत में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में जातिप्रथा किसी न किसी रूप में व्याप्त है, जो एक गंभीर सामाजिक कुरीति है।

वैदिक काल में वर्ग-विभाजन किया जाता था जिसे वर्ण व्यवस्था कहा जाता था। यह जातिगत न होकर गुण एवं कर्म पर आधारित था। समाज चार वर्गों में विभाजित था। ब्राह्मण धार्मिक तथा वेदों से जुड़े कार्य करते थे। क्षत्रिय को देश की रक्षा तथा प्रशासन से जुड़े कार्य का दायित्व था। वैश्य कृषि और व्यापार से जुड़े कार्य करते थे, तथा शूद्र को इन तीनों वर्णों की चाकरी करनी पड़ती थी। वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था में सबसे बड़ा अंतर यह है कि वर्ण का निर्धारण व्यवसाय से होता था, जबकि जाति का निश्चय जन्म से होता था। इस प्रकार जाति प्रथा भ्रष्ट सिद्ध होती गई।

जयप्रकाश नारायण ने एक बार कहा था कि “जाति भारत में एक महत्वपूर्ण दल है।” हरेल्ड गोल्ड के अनुसार “राजनीति का आधार होने की बजाय जाति उसको प्रभावित करने वाला एक तत्व है।” जातीय व्यवस्था भारतीय समाज का एक परम्परागत तत्व है । प्रो. रुडोल्फ के अनुसार भारत राजनीतिक लोकतंत्र के संदर्भ में जाति वह धुरी है, जिसके माध्यम से नवीन मूल्यों और तरीकों की खोज की जा रही है। यथार्थ में यह एक ऐसा माध्यम बन गयी है कि इसके जरिए भारतीय को लोकतांत्रिक राजनीति की प्रक्रिया से जोड़ा जा सकता है। प्रो. रजनी कोठारी अपनी पुस्तक "कास्ट इन इण्डियन पॉलिटिक्स" में भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका का विस्तृत विश्लेषण किया है। उनका मत है कि बार बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि क्या भारत में जातिप्रथा खत्म हो रही है? इस प्रश्न के पीछे यह धारणा है कि मानो जाति और राजनीति परस्पर विरोधी संस्थाएँ हैं।

जाति और राजनीति में आपसी संबंध:

भारत में जाति और राजनीति में आपसी संबंध को समझने के लिए चार प्रमुख बिन्दुओं को समझना आवश्यक है:

1. भारत में सामाजिक व्यवस्था का संगठन ही जाति के आधार पर हुआ है। राजनीति केवल सामाजिक संबंधों की अभिव्यक्ति मात्र है, इसलिए सामाजिक व्यवस्था राजनीति का स्वरूप निर्धारित करती है।

2. लोकतांत्रिक समाज में राजनीतिक प्रक्रिया जातीय संरचनाओं को इस प्रकार प्रयोग में लाती है, ताकि उनका सहयोग और समर्थन के द्वारा अपनी राजनीतिक स्थिति को और भी अधिक मजबूत बना सके।

3. भारतीय राजनीति सदैव जाति के इर्द-गिर्द घूमती है; यदि किसी व्यक्ति विशेष को राजनीति में सफलता चाहिए तो वह किसी संगठित जाति का सहारा लेता है।

4. वर्तमान में जाति विशेष का संगठन ही ज्यादातर राजनीति में भाग ले रही है। अतः स्पष्ट है कि वर्तमान में जाति का विशेष महत्व राजनीति में है। समाज के विभिन्न वर्गों तथा जातियों का समर्थन पाने के लिए राष्ट्रीय आंदोलन के नेता उन सब संस्थानों के खिलाफ थे।

भारत की जनता जातियों के आधार पर संगठित है अत: न चाहते भी राजनीति को जाति सस्था का उपयोग करना ही पडेगा। राजनीति मे जातिवाद का अर्थ जाति का राजनीतिकरण है। जाति को अपने दायरे में खींचकर यजनीति उसे अपने काम में लाने का प्रयत्न करती है। दूसरी और राजनीति द्वारा जाति या बिरादरी को देश की व्यवस्था

में भाग लेने का मौका मिलता है। राजनीतिक नेता सत्ता प्राप्त करने के लिए जातीय संगठन उपयोग करते हैं और जातियों के रूप में उनको बना-बनाया संगठन मिल जाता है जिससे राजनीतिक संगठन मे आसानी होती है। भारत में जाति और राजनीति में आपसी सम्बध को समझने हेतु इन चार तथ्यों पर विचार आवश्यक है; प्रथम, भारतीय सामाजिक व्यवस्था का संगठन जाति के आधार पर हुआ है।

राजनीति केवल सामाजिक सम्बंधो की अभिव्यक्ति मात्र है इसलिए सामाजिक व्यवस्था राजनीतिक का स्वरूप निर्धारित करती है। द्वितीय, लोकतान्त्रिक समाज मे राजनीतिक प्रक्रिया प्रचलित जातीय संरचनाओं को इस प्रकार प्रयोग में लाती है कि उनका पूर्ण समर्थन प्राप्त करके अपनी स्थिति को और अधिक शक्तिशाली बनाया जाये। तृतीय, भारत की राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में यह कहना सही होगा कि भारतीय राजनीति 'जाति' के इर्द-गिर्द घूमती है। यदि किसी व्यक्ति को राजनीतिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करनी है तो उसे अवश्य किसी संगठित जाति का सहारा लेना पड़ता है। चतुर्थ, वर्तमान समय में, जातियाँ ही संगठित होकर प्रत्यक्ष रूप से राजनीति में भाग लेती हैं तथा राजनीतिक शक्तियाँ बन जाती हैं। अत: स्पष्ट है कि जाति और राजनीति के मध्य अन्त:क्रिया पाये जाने का परिणाम यह हुआ है कि "बजाय राजनीति पर जाति के हावी होने के, जाति का राजनीतिकरण हो गया है।" राजनीति और जाति का संबंध गतिशील है।

भारत में विभिन्न राज्यों में चुनाव में जाति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जातिवाद का प्रभाव राज्य स्तर की राजनीति पर भी है। कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जहाँ की राजनीति जातिवाद से प्रभावित न हो। केरल, महाराष्ट्र, बिहार, आध प्रदेश, तमिलनाडु,

राजस्थान, हरियाणा आदि राज्यों की राजनीति पर जातिवाद हावी है। गुजरात व कर्नाटक राज्य में मध्यवर्गीय जातियाँ राजनीतिक सघर्ष में रत दिखायी देती है। राजस्थान भी इस घटना से अछूता नहीं है।

राजस्थान की राजनीति में जातियों का प्रभाव:

राजस्थान की राजनीति भी जाति व्यवस्था से अछूती नहीं हैं क्योंकि जाति के लौकिक संगठन के रूप विश्लेषण किया जाये तो एक ओर स्थानीय निकाय प्रशासकीय रूप में तथा दूसरी ओर जातीय गठजोड़ एवं प्रतिद्वन्द्विता राजनीतिक रूप से प्रदर्शित होती है जाति एवं राजनीति के मिश्रण से जातीय व्यवस्था का राजनीतिकरण हो रहा है और सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक सभी क्षेत्रों में राज्य राजनीति में आने वाले राजनीतिक नेताओं का वर्चस्व जातिगत होता जा रहा है। जाति के आधार पर उम्मीदवार का चयन होने लगा है और विभिन्न जाति समूह के लोग अपनी जाति के उम्मीदवार को मत देते हुये पाये जाते हैं। इन जातीय समूहों ने दबाव समूहों का रूप धारण कर लिया है।

अब तक की सभी विधानसभाओं के चुनाव नतीजों का विश्लेषण करें तो यह साफ दिखाई देता है कि राजस्थान की राजनीति भी पूरी तरह जाति से प्रभावित है वह भी मुख्य रूप से जाट व राजपूत जाति से। ये प्रमुख जातीय समूह राज्य राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति के निर्धारित कारक के रूप मे कार्य कर रहे हैं और राजस्थान की राजनीति में अपनी प्रमुख भूमिका अदा कर रहे हैं। राज्य में जातिवाद की जड़ें गहरी होती जा रही है। मंत्रियों के चयन में भी जातिवाद साफ दिखाई दे रहा है। राजनीतिक दलों में जातीय आधार पर कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता है केवल घटनाओं के आधार पर ही जातीय निष्कर्ष निकाला जा सकता है। राजनीतिक दलों में लोकसभा व विधानसभा

के लिए प्रत्याशियों के चयन और निर्वाचन में भी जातिवाद का प्रभाव साफ दिखाई दे रहा है। यद्यपि प्रतिष्ठित जातीयों में प्रतिस्पर्धा एवं गुटबन्दी बढ़ी है। ये जातीय गुट जाति के लोगों से गठबंधन करने लगे हैं, जिससे राजनीति में जातीय हितों के लगाव में कमी हुई है। इसके अतिरिक्त शिक्षा, शहरीकरण, निजीकरण इत्यादि नई आकांक्षाओं और भौतिक उन्नति की धारणाओं के अनुरूप जातिगत भावना कमजोर पड़ने लगी है और राजनीति में आधुनिकता का समावेश हुआ है, फिर भी राज्य राजनीति में जाति का प्रभाव सामाजिक एवं सांस्कृतिक एकता और विकास के लिए घातक तत्व है। अतः राजस्थान की राजनीति में जातीय दबाव समूहों की आज भी महत्वपूर्ण भूमिका है जिसे शोध विषय के चयन का आधार बनाया गया है।

वर्तमान में जातिगत समाज के हित संवर्द्धन भावना में वृद्धि हुई है और राजनीतिक लाभ प्राप्त कराने की अनौचित्यपूर्ण प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिला है जिसके परिणामस्वरूप सामाजिक एवं राजनीतिक परिदृश्य में परिवर्तन आ रहे।

राजस्थान की राजनीति में जातियों के प्रभाव के सवाल पर सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज की रिपोर्ट में राजनीतिक विशेषज्ञ महेश वर्मा कहते हैं कि जो भी इससे इनकार करता है, वह या तो झूठ बोल रहा है या उसे राज्य की राजनीति की समझ नहीं है। राज्य की जनसंख्या में 89 प्रतिशत हिंदू, 9 प्रतिशत मुस्लिम और 2 प्रतिशत अन्य धर्मों के हैं। एससी की आबादी 18 फीसदी, एसटी 13 फीसदी, जाट 12 फीसदी, गुज्जर और राजपूत 9-9 फीसदी, ब्राह्मण और मीना 7-7 फीसदी हैं।

महेश वर्मा यह भी कहते हैं कि जिस पार्टी का लक्ष्य राज्य में सत्ता हासिल करना है, उसे अन्य जाति समूहों के साथ-साथ ओबीसी का समर्थन भी हासिल करना होगा। इनके

बिना चुनाव जीतना मुश्किल है। यह आश्चर्य की बात है कि जहां राजनीतिक दल अपना अभियान जन कल्याण, योजनाओं पर केंद्रित करते हैं, वहीं टिकट जाति के आधार पर बांटे जाते हैं।

राजस्थान के उत्तर में जाट बाहुल्य है, जबकि दक्षिण में मीनाओं और गुज्जरों का बाहुल्य है। हरोती क्षेत्र में ब्राह्मणों, बनिया और जैनियों का वर्चस्व है। पश्चिम में जाटों और राजपूतों का वर्चस्व है। मत्स्य में मिश्रित आबादी है जबकि मध्य क्षेत्र में मुसलमानों, मीना, जाटों और राजपूतों का अनुपात अधिक है। मौजूदा विधानसभा में 27 राजपूत, 31 जाट और 15 गुर्जर विधायक हैं।

राजस्थान में, भाजपा परंपरागत रूप से व्यापारियों, राजपूतों (स्वतंत्र पार्टी के दिनों से) और ओबीसी के बीच लोकप्रिय रही है, जबकि कांग्रेस ब्राह्मण, जाट, मुस्लिम, गुज्जर, एससी और एसटी समुदायों के बीच लोकप्रिय रही है। लेकिन बदलते राजनीतिक परिदृश्य और मौजूदा सरकार के हर पांच साल में सत्ता से बाहर होने के चलन के कारण मतदाताओं की पसंद भी विकसित हुई है। ब्राह्मण कांग्रेस से दूर भाजपा की ओर चले गए हैं। 1998 और 2008 में अशोक गहलोत (माली समुदाय) को मुख्यमंत्री बनाने के बाद कांग्रेस समर्थक जाट पार्टी से दूर हो गए। 2018 का चुनाव कई मायनों में गुर्जर बनाम मीणा और राजपूत बनाम जाट के बीच मुकाबला है. इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वे एक साथ किसी पार्टी के लिए वोट नहीं करते हैं और पारंपरिक प्रतिद्वंद्विता का इतिहास साझा करते हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची:

- इंगोले, अनाथा. (2023). कास्ट पंचायतस एंड कास्ट पॉलिटिक्स इन इंडिया. दिल्ली: स्प्रिंजर.
- रुपावत, रामदास. (2022). भारतीय राजनीति: संस्थाएं और प्रक्रियाएं. जयपुर: रावत पब्लिकेशंस.
- शर्मा, बृज किशोर. (2021). कास्ट पॉलिटिक्स इन इंडिया सींस इंडिपेंडेंस: अ स्टडी ऑफ़ राजस्थान. जयपुर: पाठक पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स.
- भंडारी, विजय. (2021). राजस्थान की राजनीति: सामंतवाद से जातिवाद के भंवर में. दिल्ली: वाणी प्रकाशन.
- कुमार, संजय. (2021). इलेक्शंस इन इंडिया: एन ओवरव्यू. दिल्ली: राउतलेज.
- शास्त्री, संदीप कुमार, आशुतोष, सिसोदिया, यतीन्द्र सिंह. (2021). इलेक्टोरल डायनेमिक्स इन दी स्टेट्स ऑफ़ इंडिया. दिल्ली: राउतलेज.
- चेलम, के. एस. (2020). पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ़ कास्ट इन इंडिया. दिल्ली: सेज.
- यादव, योगेंद्र. (2020). मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी. दिल्ली: परमानेंट ब्लैक.
- सिन्हा, अभिनव. (2019). ऑन दी कास्ट क्वेश्चन: टुवर्ड्स अ मार्क्सिस्ट अंडरस्टैंडिंग. दिल्ली राहुल फाउंडेशन.
- मित्रा, सुब्रत के. (2014). पॉलिटिक्स इन इंडिया: स्ट्रक्चर्स, प्रोसेसेज एंड पॉलिसी. दिल्ली: ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.
- पलशीकर, सुहास और अन्य. (2014, संपा.). पार्टी कम्पीटीशन इन इंडियन स्टेट्स: इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इन पोस्ट कांग्रेस पार्टी. दिल्ली: ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.

- कुमार, संजय. (2013). चैंजिंग इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इन दिल्ली: फ्रॉम कास्ट टू क्लास. दिल्ली: सेज.
- राम, पपली. (2013). मतदान व्यवहार, जाति एवं राजनीतिक चेतना. दिल्ली: हिंदी बुक सेंटर.
- शाह, घनश्याम. (2012). कास्ट एंड डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन इंडिया. दिल्ली: परमानेंट ब्लैक.
- जेफ़रलोट, क्रिस्टोफे. (2011). रिलीजन, कास्ट एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया. दिल्ली: ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.
- कोठारी, रजनी. (2010). कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स. दिल्ली: ओरिएंट ब्लैकस्वान.
- लोढ़ा, संजय. (2009). एक्सप्लोरिंग इश्यूज ऑफ़ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इन राजस्थान. मध्यप्रदेश जर्नल ऑफ़ सोशल साइंसेज, वॉल्यूम-14, न.-02, दिसंबर, पेज 7-10.
- बाजोरिया, जयश्री. (2009). भारत की चुनावी राजनीति. न्यूयॉर्क: विदेश सम्बन्ध परिषद.
- मोहन, अरविन्द. (2009). लोकतंत्र का नया लोक: चुनावी राजनीति में राज्यों का उभार. दिल्ली: वाणी प्रकाशन.
- श्रीनिवास, एम. एन. (2004). कास्ट: इट्स ट्विनटीथ सेंचुरी अवतार. दिल्ली: पेंगुइन बुक्स.
- गहलोत, एन. एस. (2003). रिफ्लेक्शंस ऑन दी 12 असेंबली इलेक्शंस ऑफ़ राजस्थान. दी इंडियन जर्नल ऑफ़ पॉलिटिकल साइंस, वॉल्यूम-64, न.-3/4, जुलाई-दिसंबर, पेज 191-202.
- रॉय, मीनू. (2000). भारत में चुनावी राजनीति. दिल्ली: दीप और दीप प्रकाशन.
- गुप्ता, दीपांकर. (2000). इंट्रोगेटिंग कास्ट: अंडरस्टैंडिंग हेरार्की एंड डिफरेंस इन इंडियन सोसाइटी. दिल्ली: पेंगुइन बुक्स.

- बेली, सुसान. (1999). कास्ट, सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया: फ्रॉम दी ट्वंटिथ सेंचुरी टू दी मॉडर्न एज. लंदन: केम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस.
- चौधरी, एस. डी. (1992). इलेक्शंस एंड इलेक्टोरल बिहैवियर इन इंडिया. दिल्ली: कांति पब्लिकेशंस
- सिसन, रिचर्ड. (1971). कांग्रेस पार्टी इन राजस्थान. कैलिफोर्निया: कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी प्रेस.